

#31 वोट वापसी स्वास्थ्य मंत्री

मौजूदा व्यवस्था में स्वास्थ्य मंत्री गेजेट में ऐसे कानून छापता है जिससे फार्मा एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिकों को मुनाफा हो। कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्रियों ने बाध्यकारी लॉकडाउन, बाध्यकारी मास्क एवं बाध्यकारी टीकाकरण जैसे कई गलत कानूनों की सिफारिश की। इस कानून के लागू होने के बाद यदि स्वास्थ्य मंत्री नागरिकों को नुकसान देने वाले कानून लागू करता है तो राज्य के मतदाता वोट वापसी पासबुक का प्रयोग करके उसे किसी भी समय बदल सकेंगे। इस प्रस्तावित कानून का पूरा ड्राफ्ट इस लिंक पर देखें – Tinyurl.com/VvpHealthMinister



स्वास्थ्य मंत्री को बदलने की प्रक्रिया के मुख्य बिंदु निचे दिए हैं

- (1) स्वास्थ्य मंत्री के लिए आवेदन : 30 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक यदि स्वास्थ्य मंत्री बनना चाहता है तो वह कलेक्टर को ऐफिडेविट प्रस्तुत कर सकता है। कलेक्टर 10,000 रु का शुल्क लेकर उसे स्वास्थ्य मंत्री का प्रत्याशी घोषित करेगा, और ऐफिडेविट को मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा।
- (2) यह कानून आने से प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। तब यदि आप स्वास्थ्य मंत्री के काम से संतुष्ट नहीं हैं, और उसे बदलना चाहते हैं तो पटवारी कार्यालय में स्वीकृति के रूप में अपनी हॉ दर्ज करवा सकते हैं। आप अपनी हॉ SMS, से भी दर्ज करवा सकेंगे। आप किसी भी दिन अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, या इसे रद्द कर सकते हैं। यह स्वीकृति आपका वोट नहीं है। बल्कि यह विधायकों को दिया गया आपका एक सुझाव है।
- (3) यदि स्वास्थ्य मंत्री पद के किसी प्रत्याशी को राज्य की मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं (कुल मतदाता, न कि केवल वे जिन्होंने स्वीकृति दर्ज की है) के 25% मतदाताओं की स्वीकृतियां प्राप्त हो जाती हैं, और यदि यह स्वीकृतियां पदासीन स्वास्थ्य मंत्री से 1% अधिक भी हैं, तो मुख्यमंत्री मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री को निकाल कर सबसे अधिक स्वीकृति पाने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त कर सकते हैं, या नहीं भी कर सकते हैं।

[टिप्पणी : यदि सबसे अधिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला व्यक्ति मौजूदा विधानसभा / विधान परिषद् का सदस्य नहीं है तो अमुक व्यक्ति मंत्री बनने के बाद आगामी 6 माह में होने वाले किसी भी चुनाव या उपचुनाव में विधायक का चुनाव लड़ कर विधायक बन सकता है]

इस कानून को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने की या संसद / विधानसभा से पास करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री इसे सीधे गेजेट में प्रकाशित करके सभी राज्यों में लागू कर सकते हैं। मुख्यमंत्री चाहे तो इसे अपने राज्य में लागू कर सकते हैं। यह कानून आने के बाद विधायकों में स्वास्थ्य मंत्री बनने की प्रतिस्पर्धा शुरू होगी और वे अच्छे एजेंडे जैसे खाद्य सामग्री में बढ़ती रासायनिक मिलावट को रोकना, सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाना आदि जन हित के मुद्दों के साथ नागरिकों के समक्ष आना शुरू करेंगे ताकि नागरिक उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाने के लिए स्वीकृतियां दे सकें। इस तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियों का गठजोड़ स्वास्थ्य मंत्री से टूट जायेगा।